प्रेषक.

डा० एम०सी० जोशी, अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।

सेवा में.

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक. उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0. देहरादन।

कर्जा विभाग,

देहरादून: दिनांक: २५ नवम्बर, 2005 ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु REC से प्राप्त ऋण के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2005–08 में वित्तीय स्वीकृति।

भहोदय.

विषय:-

जपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः (1561/04)566/नाँ—3—ऊर्जा/आर०ई०सी०-ए०आर०ई०पी /03, दिनांक 7—4—2004 एवं संख्या 5556 76/2005-06(1)/23/03, दिनांक >2 11,2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005—06 में निम्नांकित जनपदों में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु व्यय वहन के लिये अगली किशत के रूप में श्री राज्यपाल महोदय रू० 2,58,92,400/— (रू० दो करोड़ अट्डावन लाख ब्यानचे हजार चार सी मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की सहर्ष रवीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त धनराशि के सम्बन्ध में REC से ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विभिन्न योजना कोड संख्या के रूप में स्वीकृत कुल ऋण एवं तदकम में अवमुक्त प्रथम अधिम किरत के समय इंगित REC की सभी शर्तो के प्राविधानानुसार उपलब्ध करायों जा रही है। REC से ग्राप्त ऋण के सम्बन्ध में राज्य शासन, UPCL (लाभाशी) एवं REC के मध्य हस्ताक्षर किये गये अनुबन्ध एवं हाईपोधिकेशन अनुबन्ध की सभी शर्तो का पालन UPCL

द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि INEC से स्वीकृत निम्नलिखिल आमीण विद्युतीकरण योजनाओं के सापेक्ष चिन्हित गांवों/तोकों के विद्युतीकरण एवं सम्बन्धित योजना में बणित बिद्युतीकरण से सम्बन्धित कार्यों के व्यय वहन हेतु इस प्रकार किया जायेगा कि स्वीकृत योजना में उल्लिखित न्यूनतम समयाविध में विद्युतीकरण एवं वर्णित सभी कार्यों को शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा।

क०संव	योजना कोड संख्या	कुल ऋण धनराशि (हजार रु० में)	जनपद
01-	58003700	1750.0	नैनीताल
02-	58003800	1094,9	बागेश्वर
03-	58004000	880,3	पिथौरागढ
04-	58004100	2323.1	पिथारागढ
05-	58004200 -	760,4	विधीरागद
06-	58004300	322.5	पिथौरागढ
07	\$8004400	4144.7	धागेश्वर
-80	58004500	821.1	वागेश्वर
09-	58004600	8561.1	पिथोरागढ
10-	58003800	1845.4	वागेष्टवर
11-	58004300	563.9	पिथीरागढ
12-	58004400	2275.5	बागेश्वर
13-	58004500	549,5	वागेश्वर
योग:- 25892.4			

4. उक्त जनपदों में इस बोजना-के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चुने गयं ग्रामों/तोकों की सूची तत्काल शासन, सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जायेगी तथा सम्बन्धित ग्राम के ग्राम प्रधान को भी सूचित किया जायेगा कि उनके किस गांव/तोक का विद्युतीकरण इस योजना के अधीन कब तक किये जाने का लक्ष्य है, वहां न्यूनतम कितने विद्युत संबोजन किस श्रेणी के दिये जाने हैं एवं क्या-क्या अन्य कार्य समिगलित है। सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को भी श्रेणीवार विद्युत संयोजन दिये जाने एवं किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाव।

5. उत्तरांघल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रत्येक दशा में REC से सम्बन्धित योजनाओं के लिये ऋण रवीकृति की सूचना सम्बन्धी REC के पत्रों के संलग्नक A व B (पूर्व में निर्मत शासनादेश के साथ संलग्न) में इंगित सभी शर्तों की शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी। इसमें त्रुटि की दशा में उत्तरांचल पावर

कारपोरेशन लि0 एवं उनके सम्बन्धित अधिकारियों की व्ववितगत जिम्मेदारी होंगी।

6. UPCL द्वारा योजना के अधीन विद्युतीकरण का कार्य समय से पूर्ण कर REC से तत्काल एवं समय से प्रतिपूर्ति दाया प्रस्तुत कर सम्पूर्ण योजना के लिये स्वीवृत ऋण के समयुल्य धनराशि की समय से प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी एवं जहां सम्बन्धित कार्या की पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी, उसे UPCL द्वारा अपने श्रोतों से वहन किया जायेगा।

- 7. प्रामों/तोकों के विद्युतीकरण/बोजना में वर्णित सुविधाओं के सृजन के पश्चात् सम्बन्धित प्राम प्रधान से नियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर REC व शासन को प्रेषित किया जायेगा, जैसा कि योजना की शर्तों में वर्णित है। साथ ही विद्युतीकरण उपरान्त ग्रामों/तोकों की सूची सम्यान्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जायेगी, जो अपने स्तर से इसका सत्यापन कर सकेगें। जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्तानुसार सत्यापन में पाई गई किसी त्रृटि या कभी तथा सत्यापन का विवरण UPCL, एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि सूची का प्रकाशन 20 सूत्रीय कार्यक्रम का अभिन्न अंग है तथा उसमें शिथिलता मान्य नहीं हैं।
- REC द्वारा स्वीकृत योजना में सम्बन्धित ग्रामों/तोकों के वियुत्तीकरण के साध—साथ योजना में इंगित निर्धारित संख्या में विद्युत संयोजनों/भार की प्राप्ति, जैसा कि पूर्व निर्गत शासनादेश के संलग्नक में वर्णित है, भी अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

9. नियत अवधि में कार्व पूर्ण न होने पर व्याज की अतिरिक्त देयता की जिम्मेदारी UPCL/UPCL के

सम्बन्धित अधिकारियों की होगी।

10. ऋण एवं ब्याज की समय से वापसी उत्तरांबत पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा शासन को इस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी कि शासन द्वारा ऋण एवं ब्याज की वापसी आर.ई.सी. को समय से की जा सके। गोरेटोरियम की अविध में देय ब्याज का समय से मुगतान भी उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा शासन को उक्तानुसार सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा भुगतान के विवरण साक्ष्य सहित शासन को यथासमय उपलब्ध करावे जायेगे और ब्याज की धनराशि संवित निधि में जमा कराने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा आर.ई.सी. का ब्याज व्यापस किया जायेगा।

11. नियत अविधि पर म्नलन / वापसी न करने घर 2.75 प्रतिशत चक्वृद्धि ब्याज दण्ड के रूप में अतिरिक्त देय होगा तथा 6 माह से अधिक भगतान / वापसी में कृत की दशा में योजना का विशेष स्वरूप समाप्त हो जायेगा, जिस दशा में ऋण पर सामान्य ब्याज (ऋण स्वीकृति के समय प्रचलित) लगेगा। अतः उत्तराचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रत्येक दशा में बोजना का सपादन / कियान्वयन निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्ती के अनुसार समय रो करते हुये नियत तिथि तक किश्त व ब्याज की चारी प्रत्येक दशा में भुगतान किया जाना सुनिश्चित

किया जायेगा।

12. योजना में इस किश्त आहरण के बाद यदि कोई अगला प्रतिपूर्ति दावा नियत अवधि में REC को प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तो किश्त में अवमुक्त सम्पूर्ण ऋण की तांश को ब्याज / दण्ड ब्याज सहित REC को वापस किया जायेगा।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित समय में उपयोग कर उस धनराशि से योजनावार कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार व राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिवा जायेगा, ताकि आधामी किश्त प्राप्त होने में विलम्ब न हो।

4000000

एवल स्वीकृत राशि पर आर०ई०सी० के पत्र रां० REC/FIN/LOAN/GoU/2004-05/02/13978
दिनांक 06.10.2005 में धनराशि अवमुक्ति तिथि के अनुसार ब्याज की देयता 06.10.2005 से आगणित होगी।

15. किस्तों एवं ब्याज की बापसी नियत तिथि से पूर्व अवस्य कर दिया जाय एवं इस हेतु नोटिस/सूबना का इन्तजार न किया जाय। धनराशि सीधे REC को भुगतान करते हुवे शारान को सूचना संसमय दी जाय।

इन्तजार न किया जाय। धनराशि सीधे REC की भुगतान करते हुय शासन की सूचना संसमय दो जाय। 16. UPCL द्वारा प्रत्येक म्ह में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य सरकार के पक्ष में जमा की जाने वाली समस्त धनराशिया जैसे विद्युत ट्रेडिंग, नि.शुल्क विद्युत के साधेज गुगतान, विद्युत शुल्क, राज्य सरकार के सापेज लियत ऋणों के मूलधन व ब्याज आदि का भुगतान प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लिया जायेगा और इस हेतू विस्तृत विवरण भी शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

17. रवीकृत की जा रही धनराशि का आहरण बीजक पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 के हरताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त कोषागार में प्रस्तुत कर किया

आयेगा।

18. स्वीकृत की जा रही धनशशि का व्यय बालू कितीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801-विजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-05-परिषण एवं वितरण-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों व अन्य उपकर्मों में निवेश-आयोजनागत-04-उत्तरांचल पावर कारपोरेशन को ग्रामिण विद्युतीकरण हेतु आरवईंठसीठ से ऋण-(0104 से स्थानान्तरित)-00-30-निवेश/ऋण के गामे डाला जायेगा।

2— यह आदेश विस्त विभाग के अशासकीय सं0— 120/XXVII-2/2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2005 द्वारा प्राप्त जनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डाठ एम0सी0 जोशी) अपर सचिव

5539

संख्याः 🛕 /1/2005-06(1)/23/03,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित:-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल ।

2— प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को माठ मंख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।

3- निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।

4- निजी सचिव-मुख्य सचिव को मुख्य सविव के संज्ञान हेतु।

5- जिलाधिकारी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़।

6- वरिष्ठ कोमाधिकारी, देहरादून।

7- सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, उत्तरांचल, देहरादून।

8- सिवव, नियोजन विभाग।

9- वित्त अनुभाग-2

10-प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।

11-बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, सविवालय परिसर, देहरादून।

12-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(डा० एम०सी० जोशी) अपर सचिव